requirements of High Tension Insulators and to examine various expansion schemes etc., has completed his work and submitted his report; and

(b) if so, whether a copy thereof will be laid on the Table of the House?

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Kanungo): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. All such reports brought out under the U.N. auspices pertain to the "Restricted Series" and as such they cannot be made public.

Shri T. B. Vittal Rao: May I know if the expenses of this expert will be met by the Government of India or by the United Nations Organisation?

Shri Kanungo: Mainly by the United Nations Organisation.

A.I.R.

*1039. **Shri Ram Shankar Lal:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to re-organise the programmes of the All India Radio;

(b) if so, the main features of the scheme; and

(c) how these are to be implemented?

The Minister of Information and Broadcasting (Dr. Keskar): (a) No, Sir. There is no new proposal for this purpose. The work of programme improvement is going on as a continuous and day to day process.

(b) and (c). Do not arise.

सामुदायिक रेडियो

*१०४२. **श्री भागवत झा आजाद:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २२ फरवरी, १९५५ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में केन्द्रीय पूल में से बिहार को कितने सामुदायिक रेडियो दिए जाने वाले हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): विभिन्न राज्य सरकारों को सामुदायिक रेडियो देने के लिए कोई केन्द्रीय पूल नहीं है। राज्यों के सूचना मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें यह योजना स्वीकृत हुई थी कि राज्य द्वारा खरीदे गए प्रत्येक रेडियो के लिए उसकी कीमत के ५० प्रति शत के बराबर अनुदान दिया जाएगा, किन्तु यह शर्त रखी गई थी कि जो रेडियो खरीदे जाएं वह स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन जो केन्द्रीय रिसर्च डिपार्टमेंट बनावे उसी के अनुसार खरीदे जाएं। इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में बिहार राज्य की आवश्यकताओं की सूचना मिल चुकी है और अन्य राज्यों की आवश्यकताओं के साथ उस पर भी विचार किया जाएगा।

श्री भागवत झा आजाद: क्या मैं जान सकता हूं कि बिहार सरकार ने अपनी आवश्यकताओं की जो सूचना आपके पास भेजी है वह क्या है?

डा० केसकर: करीब १४००।

श्री भागवत झा आजाद: क्या मैं जान सकता हूं कि जो योजना केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को सहायता देने के लिए बनाई है उसमें कुछ आवश्यक शर्त रखी हैं कि जिसके अनुसार देहातों में वह सेट बांटे जाएंगे?

डा० केसकर: केन्द्रीय सरकार ने केवल दो शर्तें लगाई हैं। एक शर्त तो यह है कि जो सेट खरीदे जाएं वह जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाया गया है वैसे ही होने चाहिएं ताकि वह मजबूत हों और आसानी से खराब न हो जाएं, और दूसरी शर्त जो लगाई है वह यह कि प्रान्तीय सरकार मेनटिनेंस के लिए कोई ऐसा इन्तिजाम करे कि यह देखा जाए कि सेट ठीक चल रहे हैं, और उनकी बैटरीज ठीक से चल रही हैं या नहीं यह देखा जाए।

श्री भागवत झा आजाद: इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार समूचे देश में अनुमानतः कितने सेटों के लिए अनुदान देगी?